भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1469

जिसका उत्तर 13 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

उद्वह सिंचाई प्रणाली

1469. श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

श्री संजय उत्तमराव देशमुख:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में और विशेषकर महाराष्ट्र के परभणी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के किसानों को सिंचाई के लिए पानी किस प्रकार उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) क्या सरकार का विचार सभी गांवों और किसानों को सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने के लिए उद्वह (लिफ्ट) सिंचाई प्रणाली लागू करने का है;

(ग) यदि हां, तो अब तक महाराष्ट्र और विशेष रूप से वाशिम-यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में उद्वह सिंचाई प्रणाली से कितने किसानों और गांवों को लाभ हुआ है और इसके क्या नीति अपनाई गई है;

(घ) सरकार द्वारा महाराष्ट्र के परभणी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र और वाशिम-यवतमाल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में पुसाद तहसील के ईसापुर बांध क्षेत्र के 42 गांवों को उद्वह सिंचाई प्रणाली के माध्यम से पानी उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा क्षेत्रीय किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलबध कराने हेतु कौन-से अन्य कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क): प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) वर्ष 2015-16 के दौरान आरंभ की गई थी, जिसका उद्देश्य खेत में पानी की भौतिक पहुँच में वृद्धि करना और सुनिश्चित सिंचाई के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेत में जल उपयोग दक्षता में सुधार करना, स्थायी जल संरक्षण पद्धतियों को आरंभ करना आदि है। पीएमकेएसवाई एक व्यापक योजना है, जिसमें इस मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किए जा रहे दो प्रमुख घटक शामिल हैं, नामतः त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)। वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 की अवधि के लिए पीएमकेएसवाई के कार्यान्वयन को भारत सरकार द्वारा दिसंबर, 2021 में मंजूरी दी गई है।

वर्ष 2016-17 से पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत 115 वृहद, मध्यम और विस्तारित, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण परियोजनाएं (7 चरणों सहित) शामिल की गई हैं। पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत 63 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और देश में 26.27 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है। इसके अलावा, एचकेकेपी के कमान क्षेत्र विकास और जल प्रबंधन घटक के अंतर्गत 19.28 लाख हेक्टेयर कमान क्षेत्र विकसित किया गया है।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के अंतर्गत महाराष्ट्र की 28 वृहद एवं मध्यम परियोजनाएं शामिल की गई हैं, जिनमें से 02 परियोजनाएं निचली धुदना परियोजना और ऊपरी पेन गंगा परियोजना से परभणी जिला लाभांवित हो रहा है। इन परियोजनाओं के अंतर्गत 85,577 हेक्टेयर सिंचाई क्षमता सृजित की गई है और 39,161 हेक्टेयर कमान क्षेत्र विकसित किया गया है।

इसके अलावा, महाराष्ट्र की 8 एमएमआई और 83 सतही लघु सिंचाई (एसएमआई) परियोजनाओं का कार्य पूरा करने के लिए एक विशेष पैकेज को मंजूरी दी गई है, जिसकी अनुमानित शेष लागत अप्रैल, 2018 तक 13,651.61 करोड़ रुपये है, जिसे भारत सरकार द्वारा 2018-19 के दौरान वित्तीय सहायता के लिए मंजूरी दी गई है। दो एमएमआई और 60 एसएमआई परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और इस योजना के तहत 1.77 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता का सृजन किया गया है।

(ख) से (घ): जल राज्य का विषय है, इसलिए लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं सहित सिंचाई परियोजनाओं की योजना बनाना, कार्यांवित करना और उनका प्रबंधन करना तथा राज्य में सिंचाई प्रणाली को और अधिक व्यापक बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करना संबंधित राज्य सरकार की जिम्मेवारी होती है। भारत सरकार की भूमिका केवल तकनीकी सहायता प्रदान करने तथा चालू योजनाओं के तहत चिन्हित परियोजनाओं हेतु आंशिक वित्तीय सहायता प्रदान करने तक सीमित है।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी के तहत महाराष्ट्र राज्य से 28 वृहद् और मध्यम परियोजनाओं को इसमे दस (10) परियोजनाओं में उपर्युक्त योजना के तहत लिफ्ट सिंचाई घटक शामिल है। इसके अलावा, विशेष पैकेज के तहत तीन (3) वृहद् और मध्यम सिंचाई परियोजनाएं भी लिफ्ट सिंचाई परियोजनाएं हैं।

पीएमकेएसवाई-एआईबीपी और महाराष्ट्र पैकेज के अंतर्गत लिफ्ट सिंचाई घटक संबंधी परियोजनाओं का विवरण, सृजित सिंचाई क्षमता और लाभान्वित जिलों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

(ङ): पीएमकेएसवाई और महाराष्ट्र पैकेज के अलावा, हाल के दिनों में सिंचाई क्षमता के सृजन और सिंचाई के लिए जल उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार की कुछ प्रमुख पहल नीचे दी गई हैं।

1. जून, 2018 में भारत सरकार ने जम्मू-कश्मीर और पंजाब को लाभ प्रदान करने वाली शाहपुरकंडी बाँध (राष्ट्रीय) परियोजना के लिए 2,715.70 करोड़ रुपये की परियोजना लागत

हेतु, वित्तीय सहायता को मंज़ूरी दी है। परियोजना के लिए स्वीकृत केंद्रीय सहायता देयता 485.38 करोड़ रुपये है।

2. सितंबर, 2018 में भारत सरकार ने पंजाब और राजस्थान राज्यों को लाभ पहुँचाने वाली राजस्थान फीडर और सरहिंद फीडर की रीलाइनिंग के लिए 1976.75 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत पर वित्तीय सहायता को मंजूरी दी है। इस परियोजना के लिए स्वीकृत केंद्रीय सहायता देयता 982 करोड़ रुपये है।
3. दिसंबर, 2021 में भारत सरकार ने हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में क्रमशः रेणुकाजी बांध और लखवार बहुउद्देशीय (राष्ट्रीय) परियोजनाओं के लिए केंद्रीय सहायता को मंजूरी दी है। इन दोनों परियोजनाओं की अनुमानित लागत क्रमशः 6,946.99 करोड़ रुपये और 5,747.17 करोड़ रुपये है।
4. दिसंबर, 2021 में भारत सरकार ने मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में 44,605 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से केन-बेतवा लिंक परियोजना को भी मंजूरी दी है।

*****

अनुलग्नक

"उद्वह सिंचाई प्रणाली" के संबंध में दिनांक 13.02.2025 को लोक सभा में उत्तर दिए जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 1469 के भाग (ख) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

महाराष्ट्र में लिफ्ट सिंचाई घटक संबंधी परियोजनाओं की सूची

क. पीएमकेएसवाई-एआईबीपी

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अप्रैल, 2016 से जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	लिफ्ट घटक सहित मार्च 2024 तक निर्मित सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)	लाभान्वित जिले
चालू परियोजनाएं				
1	वाघुर परियोजना	195.02	32.06	जलगांव
2	निचली वर्धा परियोजना	216.63	56.42	वर्धा
3	कुडाली मध्यम सिंचाई परियोजना	5.90	0.23	सतारा
4	जिहे कथापुर परियोजना	110.86	8.53	सतारा
5	बोडवाड परिसर सिंचन योजना चरण-I	0	0	जलगांव और बुलढाना
पूर्ण परियोजनाएं				
6	कृष्णा कोयना एलआईएस	303.86	106.74	सोलापुर और सांगली
7	बेम्बला परियोजना	285.22	50.60	यवतमाल
8	गदनदी परियोजना	3.49	5.18	रत्नागिरि
9	खड़कपूर्णा परियोजना	40.16	23.86	बुलढाना
10	ताराली परियोजना	72.06	15.47	सतारा

ख. महाराष्ट्र पैकेज

क्रम सं.	परियोजना का नाम	अप्रैल, 2018 से जारी केंद्रीय सहायता (करोड़ रुपए में)	मार्च 2024 तक निर्मित सिंचाई क्षमता (हजार हेक्टेयर)	लाभान्वित जिले
चालू परियोजनाएं				
1	सुलवाडे, जामफाल कनोली लिफ्ट सिंचाई योजना	464.15	निर्मित की जानी है	धुले
पूर्ण परियोजनाएं				
2	तेम्भू एलआईएस	297.16	96.32	सतारा, सांगली और सोलापुर
3	घुंघसी बैराज एलआईएस	36.06	5.10	अकोला

*****